



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102023-249168
CG-DL-E-05102023-249168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]

नई दिल्ली मंगलवार, अक्तूबर 3, 2023/ आश्विन 11, 1945

No. 251]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ ASVINA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

मामला सं. एडी(ओआई) 18/2023

विषय: जापान, रूस, सिंगापूर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हालोबुटाइल रबड़ (एचआईआईआर)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 6/19/2023-डीजीटीआर.-1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "एडी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, रिलायंस सिबूर इलेस्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने जापान, रूस, सिंगापूर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हालोबुटाइल रबड़ (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद"

अथवा “एचआईआईआर” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से बाधित किया है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद हालोबुटाइल रबड़ (एचआईआईआर) है जैसे ब्रोमोबुटाइल रबड़ (बीआईआईआर) अथवा क्लोरोबुटाइल रबड़ (सीआईआईआर) हैं। एचआईआईआर को आईआईआर के आइसोप्रीन समूह के हेलोजिनेशन के जरिए प्राप्त किया जाता है जिसमें उन्नत गुणों और विशेषताओं का रबड़ उत्पादित होता है। एचआईआईआर को टायर इनर लाइनर, होज, सील, मैम्बरेन्स, टैंक लाइनिंग, कन्वेयर बेल्ट, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग और खेल सामानों के लिए बाल ब्लैडर जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत टैरिफ कोडों 4002 39 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के बीच कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं रखते हैं। आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की “समान वस्तु” माना जा रहा है।

6. विषय की जांच में इच्छुक पक्ष इस जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। आवेदक ने आगे बताया है कि यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी में विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक अर्थात् पीजेएससी अर्थात् पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम से संबंधित है। इसके अलावा यह पहले भी सिबुर टोगलियाटी से संबंधित था, जिसे टैटनैफ़्ट को बेच दिया गया है। तथापि, भारत को ऐसे उत्पादों का कोई सीधा निर्यात नहीं हुआ है। निर्यात, यदि कोई हो, तो व्यापारियों के द्वारा किए गए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास अधिकांश शेयर हैं और तदनुसार, वह रिलायंस सिबुर इलास्टोमर प्राइवेट लिमिटेड पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा, आवेदक और निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम को नियम 2(ख) के अंतर्गत संबंधित नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये दोनों कंपनियां कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से एक दूसरे को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं। तीसरी कंपनी को संयुक्त रूप से नियंत्रित नहीं करती हैं और तीसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। तदनुसार, आवेदक ने दावा किया है कि उसे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं समझा जाना चाहिए।

8. रिकॉर्ड में सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिलायंस इलास्टोमर प्राइवेट लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी प्रथमदृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू

उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमत से संबंधित साक्ष्य उसे नहीं मिल पाए थे। तथापि, जापान और यू एस ए के लिए आयात कीमत से संबंधित सूचना उपलब्ध थी जो निर्यातक देश में वस्तु की कीमत है। आवेदक ने इस आधार पर सामान्य मूल्य का साक्ष्य किया है। आवेदक ने यह बताया है कि जापान और यू एस ए को छोड़कर संबद्ध देशों के लिए उन देशों में आयात की मात्रा काफी कम थी या आयातों की कीमत उत्पादन लागत से कम थी। इस प्रकार, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं थी। तदनुसार, सामान्य मूल्य को इन संबद्ध देशों में आयात कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सका।
10. आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना यह दर्शाती है कि रूस, सिंगापुर तथा यूनाइटेड किंगडम के लिए तीसरे देशों को निर्यात कीमत की उत्पादन लागत से कम थी। अतः इन देशों में सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है।
11. प्राधिकारी ने इस जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार किया है।

ड. निर्यात कीमत

12. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत पर डी जी सिस्टम के आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित करने हेतु विचार किया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

च. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि भारतीय बाजार में संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही है और पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है जो जांच की शुरुआत को उचित ठहराता है।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

14. घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों ने उसकी स्थापना में वास्तविक बाधा पहुंचाई है। क्षति अवधि में आयातों तथा घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों संबंधी सूचना यह दर्शाती है कि आयातों ने ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है जो अन्यथा बढ़ गई होती। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसे क्षमताओं के अल्प उपयोग का सामना करना पड़ा और उसे अपने उत्पादन के निपटान के लिए निर्यात करना पड़ा और उसने अपनी बिक्री लागत से कम पर घरेलू बाजार में वस्तु बेची है। आवेदक को नकद घाटे हुए हैं और वह नियोजित पूंजी पर नगण्य आय अर्जित कर पाया है। घरेलू उद्योग का निष्पादन मात्रा और लाभप्रदता दोनों मापदंडों की दृष्टि से अनुमानित से काफी कम रहा है। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा

और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. संबद्ध देश

16. आवेदक ने यूरोपीय संघ, जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन किया है। तथापि, प्राधिकारी को प्राप्त डी जी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ से आयात की मात्रा समान उत्पाद के आयातों के 3 प्रतिशत से कम है। तदनुसार, वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश जापान, रूस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) हैं।

ञ. जांच की अवधि

17. आवेदन में जनवरी-दिसंबर, 2022 पर जांच अवधि के रूप में विचार करते हुए सूचना दी गई है। आवेदक ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ 2019-20, 2020-21 और 2021-22 तथा प्रस्तावित जांच की अवधि के लिए आंकड़े दिए हैं। तथापि, नियमावली के नियम 5(3क) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-2022, और पीओआई की अवधि शामिल हैं।

ट. प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

19. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adv13-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
20. संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ड. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv13-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे की या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है

या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
27. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
29. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।
31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
33. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें। अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

त. असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2023

Case No – AD(OI) – 18/2023

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Halobutyl-Rubber (HIIR)” originating in or exported from Japan, Russia, Singapore, the United Kingdom and the United States of America.

F. No. 06/19/2023-DGTR.—1. Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules or AD Rules”), Reliance Sibur Elastomers Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Halobutyl-Rubber (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “HIIR”) originating in or exported from European Union, Japan, Russia, Singapore, the United Kingdom and the United States of America.

2. The applicant has alleged that dumping of imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries has materially retarded the establishment of the domestic industry. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is Halobutyl-Rubber (HIIR), such as Bromobutyl Rubber (BIIR) or Chlorobutyl Rubber (CIIR). HIIR is obtained through the halogenation of the isoprene groups of the IIR, producing a rubber with improved properties and characteristics. HIIR is used for tire inner liners, hoses, seals, membranes, tank linings, conveyor belts, protective clothing and for consumer products, such as ball bladders for sporting goods.
4. The product under consideration is classified under Chapter 40, under tariff code 4002 39 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.
5. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 30 days from the date of initiation of this investigation.

B. Like article

6. The applicant has claimed that there are no known significant differences in the goods produced by the domestic industry and those exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The applicant claimed that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as ‘like article’ to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

C. Domestic industry and standing

7. The application has been filed by Reliance Sibur Elastomers Private Limited. The applicant has stated that it has not imported the product under consideration. The applicant has further stated that it is a joint venture between Reliance Industries Limited and Sibur Investments AG. Sibur Investments AG is related to a producer of the product under consideration in Russia, namely PJSC Nizhnekamskneftekhim, through PJSC Sibur Holding. Further, it was also earlier related to Sibur Togliatti, which has been sold to Tatneft. However, there are no direct exports of such producers to India. Exports, if any, have been made by the traders. The applicant has claimed that Reliance Industries Limited holds majority shares and accordingly, exercises control over Reliance Sibur Elastomers Private Limited. Further, the applicant and PJSC Nizhnekamskneftekhim cannot be considered related under Rule 2(b) since the two entities are not in a position to legally or operationally control each other, do not jointly control a third entity, and are not controlled by a third entity. Accordingly, the applicant has claimed that it should not be considered related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries.
8. From the information on record, the Authority notes that Reliance Elastomers Private Limited is the sole producer of like article in India. The applicant accounts for a major proportion of the total domestic production in India. In view of the above and after due examination, the Authority *prima facie* notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Normal value

9. The applicant has claimed that it was not able to find evidence regarding the domestic selling price in the subject countries. However, for Japan and the USA, information with regard to import price was available, which is the price of goods in the exporting country. The applicant has provided evidence of normal value on that basis. The applicant has submitted that for the subject countries barring Japan and the USA, the volume of imports in those countries was too low, or the imports were priced below the cost of production, thereby not being in the ordinary course of trade. Accordingly, the normal value could not be determined based on the price of imports into these subject countries.
10. The information provided by the applicant also shows that for Russia, Singapore and the United Kingdom, the price of exports to third countries was also below the cost of production. Therefore, the normal value for these countries has been determined based on the basis of best available information, having regard to the cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses with reasonable profits.
11. The Authority has accepted the claim of the applicant in respect of the determination of normal value for the subject countries for the purpose of the initiation of this investigation.

E. Export price

12. The Authority has considered the export price of the subject goods has been determined by considering the price of the subject goods, as reported in the DG Systems data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, and bank charges to arrive at an ex-factory export price.

F. Dumping margin

13. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries into the Indian market and the dumping margin is above *de-minimis* so as to justify initiation of the investigation.

G. Injury and Causal link

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has claimed that the imports have materially retarded its establishment. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred. The applicant has also claimed that it has faced underutilization of capacities and has been forced to export in order to dispose of its production and has sold in the domestic market below its cost of sales. The applicant has incurred cash losses and has been able to earn a negligible return on its capital employed. The performance of the domestic industry is much lower than that projected, both in terms of volume and profitability parameters. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify the initiation of an anti-dumping investigation.

H. Initiation of anti-dumping investigation

15. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Subject countries

16. The applicant filed for initiation of an anti-dumping investigation into imports from the European Union, Japan, Russia, Singapore, the United Kingdom and the United States of America. However, as per the DG Systems data received by the Authority, the volume of imports from the European Union accounts for less than three per cent of the imports of the like products. Accordingly, the subject countries for the present anti-dumping investigation are Japan, Russia, Singapore, the United States of America and the United Kingdom (herein referred to as “subject countries”).

J. Period of investigation

17. The applicant has provided information considering January - December 2022 as the period of investigation. The applicant has provided data for the periods 2019-20, 2020-21, and 2021-22 and the proposed period of investigation for the purpose of injury analysis. However, in accordance with the provisions of Rule 5(3A) of the Rules, the period of investigation (POI) considered by the Authority for the present investigation is from 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years, 2019-20, 2020-21, 2021 -22 and the period of investigation.

K. Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

L. Submission of Information

19. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adv13-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
20. The known producers/exporters from the subject countries, their governments through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producer are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

M. Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be to the Authority via email at the email addresses adv13-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

N. Submission of information on confidential basis

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the trade notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
27. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
28. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. Inspection of Public File

34. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

P. Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority